Central Water Commission
Technical Documentation Directorate
Bhagirath(English)& Publicity Section
****

West Block II, Wing No-5
R K Puram, New Delhi – 66.

Dated 9.1.2019.

Subject: Submission of News Clippings.

The News Clippings on Water Resources Development and allied subjects are enclosed for perusal of the Chairman, CWC, and Member (WP&P/D&R/RM), Central Water Commission. The soft copies of clippings will be uploaded on the CWC website.

9.1.2019
SPA (Publicity)

Encl: As stated above.

O/C

Deputy Director, WSE Dte. 09/01/2019

Director, WSE Dte. on leave

For information to

Chairman CWC, New Delhi

Member (WP&P/D&R/R.M.), CWC and all concerned, uploaded at www.cwc.nic.in

News item/letter/article/editorial published on 09.01.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu ✓
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald
M.P.Chronicle
A a j (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

Irrigation projects delay led to jump in costs: CAG

'210 approved, only 62 completed'

SPECIAL CORRESPONDENT
NEW DELHI

Tardy implementation of projects under the Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) between 2008-2017 led to an almost threefold jump in the cost of these projects to ₹1.20 lakh crore, according to a report by the Comptroller and Auditor General (CAG), tabled in Parliament on Tuesday.

The AIBP was initiated in 1996 as a Central scheme to speed up the implementation of large irrigation projects, including dams and canals, especially those which were beyond the resource capability of the States.

The Union Ministry of Water Resources is responsible for framing policy guidelines for implementation while State Governments are associated with planning and implementing irrigation projects and schemes.

From 2008-2017, of the 201 major and medium projects approved, only 62 were completed. Of the 11,291 minor irrigation schemes sanctioned, only 8,014 were completed. As a result, only about 35% of India's irrigation potential was utilised. Of the 118 major projects surveyed by the CAG, 105 suffered from a "time overrun" with some projects being delayed by more than 18 years.

The audit of the AIBP revealed lacunae in the planning, implementation and monitoring of the programme. Projects and schemes were included under AIBP in violation of the programme's guidelines, resulting in irregular release of ₹3,718.71 crore. There were also deficiencies in the preparation and processing of Detailed Project Reports such as inadequate surveys, inaccurate assessment of water availability, Irrigation Potential and Command Area and the lack of activity-wise construction plans.

'Financial irregularities'

The CAG also pointed out "financial irregularities" such as diversion of funds amounting to ₹1,578.55 crore, parking of funds totalling ₹1,112.56 crore and "fictitious and fraudulent expenditure" of ₹7.58 crore. There were also instances of short/non-realisation of revenue amounting to ₹1,251.39 crore. "The monitoring by Central and State agencies was lax. There were shortfalls in number of monitoring visits by Central Water Commission (CWC) and reports were not prepared in all projects evaluated. Further, compliance to issues highlighted in the CWC reports were also pending."

News item/letter/article/editorial published on 09.01.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald
M.P.Chronicle
A a j (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

यमुना नदी के प्रदूषण को क्यों भूल गए हैं हम

H-9

कुछ प्रयास यमुना को लेकर भी हुए हैं, लेकिन अविरल बनाने को लेकर सारी चर्चा सिर्फ गंगा की होती है।

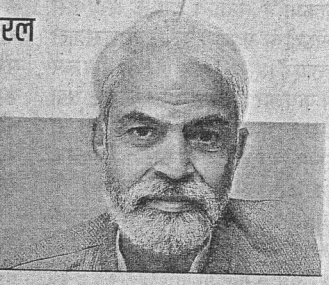

ज्ञानेन्द्र रावत
पर्यावरण कार्यकर्ता

विश्व प्रसिद्ध कुंभ प्रयागराज जिस जगह शुरू हुआ है, वहां गंगा और यमुना का संगम है। गंगा नदी की सफाई की चर्चा तो हम अक्सर करते हैं, लेकिन यमुना को आमतौर पर भुला दिया जाता है। यह बात अलग है कि तमाम दावों के बावजूद गंगा भी अभी तक साफ नहीं हो सकी है, लेकिन यमुना तो उस तरह चर्चा में भी नहीं है। यह सच है कि गंगा की तरह यमुना की शुद्धि के लिए भी अब तक कई अभियान चले और करोड़ों रुपये की राशि खर्च हो चुकी है। यमुना को टेम्स बनाने के दावे भी हुए। कई धर्मगुरु और पर्यावरण कार्यकर्ता भी इस अभियान को लेकर सक्रिय हुए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यमुना की सफाई की बात जब भी होती है, तो वह दिल्ली के आसपास ही सिमट जाती है। यह भी सच है कि यमुना को सबसे ज्यादा प्रदूषित देश की राजधानी ही करती है। मगर यहां भी इस नदी का कल्याण नहीं हो सका और अब वह नाले में तब्दील होकर रह गई है।

यमुना के 1,376 किलोमीटर लंबे रास्ते में दिल्ली का क्षेत्र सिर्फ दो फीसदी है, लेकिन यमुना में 79 फीसदी गंदगी दिल्ली ही घोलती है। अनुमान है कि दिल्ली की तकरीबन 52 हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयां यमुना को जहरीला बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। रिहाइशी इलाकों में चलने वाली ये औद्योगिक इकाइयां सीधे तौर पर अपना औद्योगिक कचरा नालों व सीवर के जरिए यमुना में गिरा रही हैं। इसके साथ-साथ राजधानी के औद्योगिक इलाकों में चल रहे कारखाने भी यमुना को प्रदूषित करने में कम दोषी नहीं हैं। इसका खुलासा एनजीटी के समक्ष यमुना की सफाई के लिए गठित समिति ने बीते दिनों अपनी रिपोर्ट में किया है। उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट घरेलू सीवर में मिलने के बाद काफी कोशिश के बाद भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी सीटीपी में शोधित नहीं हो पाता।

दिल्ली के सीटीपी की क्षमता प्रतिदिन 2,120 लाख लीटर कचरे के प्रवाह को शोधित करने की है। लेकिन हकीकत में अभी सिर्फ 520 लाख लीटर का ही शोधन हो पाता है। पल्ला से बदरपुर तक यमुना की कुल लंबाई 54 किलोमीटर है। इस बीच राजधानी का 1,390 लाख लीटर सीवर का पानी सीधे-सीधे यमुना में जाता है। इसके अलावा यमुना में गणेश चतुर्थी, दुर्गा मूर्ति विसर्जन और छठ पूजा के दौरान होने वाली धार्मिक गतिविधियों से भी प्रदूषण बढ़ा है। इस बात का खुलासा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनजीटी द्वारा गठित समिति के समक्ष किया है। बोर्ड ने समिति के समक्ष कहा है कि सिंथेटिक सामग्री से बनी और घातक रसायन युक्त पेंट से रंगी मूर्तियों के विसर्जन से यमुना में भारी धातु की सांद्रता कई गुना तक बढ़ गई है, जो सेहत के लिए काफी खतरनाक है।

यह खतरा सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, देश के उन तमाम हिस्सों के लिए है, जहां से यमुना बहती चलती है और उसके बाद सारा प्रदूषण गंगा में उड़ेल देती है। समिति ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यमुना जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही है। इसका न्यूनतम प्रवाह सुनिश्चित किए जाने तक यमुना नदी के पुनरुद्धार की संभावना नहीं है। हालत यह है कि यमुना कई जगहों पर साल में नौ महीने तक सूखी रहती है।

यमुना के पूरे रास्ते में दिल्ली का क्षेत्र महज दो फीसदी है, लेकिन राजधानी इस नदी में 79 फीसदी गंदगी उड़ेलती है।

यमुना की सफाई को लेकर कई परियोजनाएं बन चुकी हैं, लेकिन इस नदी की गंदगी भी बढ़ती ही जा रही है। यमुना नदी में, खासकर मथुरा, वृंदावन क्षेत्र में कैडमियम, लेड, निकिल, मैगनीज, जिंक, आयरन जैसी विषाक्त धातुएं पाई गई हैं। अब यमुना की सफाई को लेकर 12 संयंत्रों पर काम शुरू किया गया है। सरकार का दावा है कि यह काम पूरा होने के बाद यमुना में स्वच्छ जल का प्रवाह होने लगेगा। बताया गया है कि इन संयंत्रों का निर्माण होने के बाद यमुना में गंदा पानी प्रवाहित नहीं किया जाएगा।

यह भी सच है कि यमुना नदी दिल्ली में प्रवेश से पहले ही काफी प्रदूषित हो चुकी होती है। हरियाणा के तमाम जिलों की कई औद्योगिक इकाइयों का कचरा और उसके शहरों का सीवेज इसे काफी पहले ही जहरीला बना देता है। शुद्धि अभियान की जरूरत पूरे देश में है, लगभग देश की हर नदी में।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

News item/letter/article/editorial published on 09.01.2019 in the

Hindustan Times
Statesman
The Times of India (N.D.)
Indian Express
Tribune
Hindustan (Hindi)
Nav Bharat Times (Hindi)
Punjab Keshari (Hindi)
The Hindu
Rajasthan Patrika (Hindi)
Deccan Chronicle
Deccan Herald
M.P.Chronicle
A a j (Hindi)
Indian Nation
Nai Duniya (Hindi)
The Times of India (A)
Blitz

and documented at Bhagirath(English)& Publicity Section, CWC.

गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए सरयू की धारा मोड़ी

हिन्दुस्तान नेटवर्क

बस्ती/दुबौलिया | सुरेंद्र पांडेय/इमरान

बस्ती को बाढ़ से बचाने के लिए भागीरथ प्रयास शुरू करते हुए सरयू की धारा मोड़ दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बीडी बंधे से सटकर बहने वाली धारा को करीब चार सौ मीटर तक आधा किलोमीटर दूर पहुंचा दिया गया है। इसे एक किलोमीटर दूर पहुंचाना है।

मुख्यमंत्री की योजना 55 किलोमीटर लंबे बांध क्षेत्र में नदी को पूर्व जगह पर पहुंचाने की है। इसके लिए आंध्र प्रदेश और कानपुर के विशेषज्ञों का दल दिन-रात काम में जुटा है। विक्रमजोत-धुसवा (बीडी) बांध के 55 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में दो दशक से सरयू कहर बरपाती रही है। बाढ़ के समय बंधे के कटने का डर बना रहता है। कटरिया-चांदपुर के पास सरयू बंधे से सटकर बह रही है, जबकि दो दशक पहले पांच से सात किलोमीटर दूर थी। अगस्त 2018 में अचानक बंधे पर सरयू की कटान से अफरातफरी मच गई थी।

बाढ़ की विभिषिका को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 सितम्बर 2018 को दुबौलिया का दौरा किया था। यहीं पर उन्होंने बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान का वादा किया था। उसके बाद उन्होंने सिंचाई विभाग को नदी की धारा मोड़ कर पुराने स्थान पर पहुंचाने की योजना बनाने के निर्देश दिए।

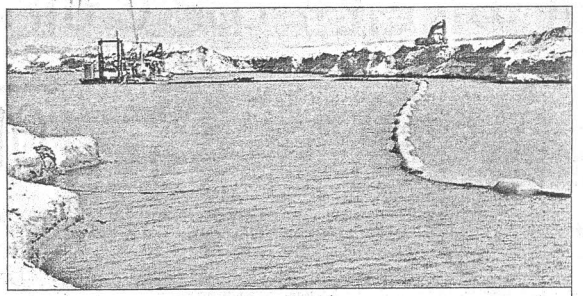

बस्ती में गांव को बाढ़ से बचाने के लिए सरयू नदी की धारा को मोड़ा गया। • हिन्दुस्तान

सीएम के निर्देश पर सिंचाई विभाग की टेक्निकल टीम कानपुर के अधीक्षण अभियंता नवीन कपूर की देखरेख में काम शुरू कर दिया है।

चार सौ मीटर दूर हटाई जा रही धारा

टेक्निकल टीम ने ड्रोन से नदी का सर्वे किया। इस आधार पर सिल्ट हटाकर नई धारा बनाने का रूट तय किया गया।

पहले चरण में कटरिया-चांदपुर के पास धारा को बांध से पांच सौ मीटर दूर हटाने का काम चल रहा है। ड्रेजर मशीन से बालू निकालकर नई धारा की जगह बनाई जा रही है तो इस बालू को बांध से सटकर बह रही मुख्यधारा को पाटा जा रहा है। मशीनों के सहारे 30 मीटर चौड़ाई में 20 फुट गहरी धारा बनाने का काम चल रहा है। यहां धारा को करीब 500 मीटर दूर कर दिया गया है।